

हर श्रमिक को मिलेगा आयुष्मान कार्ड

सीएम बोले- 12.26 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा, 15.83 लाख भी जल्द जुड़ेंगे
अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सभी श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से जोड़ेगी। अब तक 12.26 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है, जिससे उनके परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। बाकी 15.83 लाख श्रमिकों को भी जल्द इस योजना से जोड़ा जाएगा। इससे करीब 75 से 80 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य एक करोड़ श्रमिक परिवारों, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाना है।

सीएम शुक्रवार को इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालय के पहले बैच के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि इन बच्चों ने सीबीएसई की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता के



श्रमवीर गौरव समारोह

श्रमिक को सम्मानित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में मौजूद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक व श्रम मंत्री अनिल राजभर। -अमर उजाला

श्रमिक सुविधा केंद्रों का किया शिलान्यास

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में श्रमिक सुविधा केंद्रों का शिलान्यास किया, जिससे श्रमिकों को एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं मिलेंगी। ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि आवंटन पत्र दिया गया। जेवर में सीएम कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि गोरखपुर में 5 एकड़ में ईएसआईसी अस्पताल बनेगा। जहां अस्पताल नहीं होंगे, वहां श्रमिकों को आयुष्मान जैसी सुविधा मिलेगी।

श्रम की लाज रखी है। उन्होंने श्रमिकों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके पसीने से देश आगे बढ़ता है। पहले श्रमिकों के पास न घर होता था, न इलाज की सुविधा,

लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों को सम्मान व सुविधाएं मिल रही हैं।

सीएम ने कहा कि बीमा कंपनियों से बातचीत कर औद्योगिक क्षेत्रों में

मजदूरी नहीं दी तो उसका होगा काम तमाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालय में अनुभवी शिक्षकों की तैनाती की गई है, ताकि श्रमिक का बच्चा भविष्य में अधिकारी बने। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 18000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि वन नेशन-वन राशनकार्ड की सुविधा के तहत श्रमिक देश में कहीं भी अपना राशन ले सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े-बड़े शहरों में श्रमिक अड़्डे बनते थे। काम करने के बाद ठेकेदार या मालिक मजदूरी देने से मना कर देते थे या कम देते थे। अब सरकार ने साफ कहा है कि काम किया है तो उसका दाम भी मिलना चाहिए। अगर कोई मजदूरी नहीं देगा, तो सरकार उसका काम तमाम करेगी।

काम करने वाले श्रमिकों को भी 5 लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा निशुल्क देने की तैयारी की जा रही है।

>> कुछ लोग उद्योगों को करना चाहते हैं बाधित : पेज 2